

श्रीराम रेयन्स, धोरामनगर, कोटा (राजस्थान) द्वारा आयात साइसेंसों के दुरुपयोग और घांघली सम्बन्धी आरोपों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या मैसर्स श्रीराम रेयन्स ने 26 अप्रैल, 1973 को मैसर्स डाई इंची करकारिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को आयातित एथोमीन सी-25 के 48 ट्रम बेचे थे ;

(घ) क्या मैसर्स श्रीराम रेयन्स ने सरकार की अनुमति के बिना 18 जुलाई, 1972 को 8460 किलोग्राम आयातित लुगदी बेची थी ;

(ङ) क्या इस फर्म ने 5 जुलाई, 1972 को मैसर्स नूचेन प्लास्टिक लिमिटेड, फरीदाबाद को भी आयातित लुगदी बेची थी; और

(च) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) मैसर्स श्रीराम रेयन्स मिल्स, कोटा, राजस्थान के विरुद्ध 13-10-1976 को जनपद वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के श्री नागेश्वर सिंह सुपुल श्री रुद्र प्रसाद सिंह ने एक शिकायत राष्ट्रपति को भेजी थी जिसकी एक प्रति प्रधान मंत्री को भेजी गई थी। प्रधान मंत्री सचिवालय ने इस शिकायत को 5-11-1976 को वाणिज्य मंत्रालय को भेज दिया था।

(ख) से (च). इस मामले की अभी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल पूरी होने के पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो फर्म के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

Non-Utilization of Imported Groundnut Oil

4973. SHRI K. T. KOSALRAM : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 18,000 tonnes of Groundnut oil imported for distribution by Tamil Nadu Government some months ago, is lying in Bombay port unutilised ;

(b) whether it is also a fact that this oil will become unfit for human consumption if it is kept unrefined for some more time; and

(c) whether Government propose to release this oil to millers and refineries in Southern States for refining and distribution .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL)

(a) 17,300 tonnes of groundnut oil was imported for distribution to the different states, including Tamil Nadu, after assessing their demand. The oil is in STC's storage in Bombay.

(b) No, Sir.

(c) At present, considering the ruling prices of indigeno s groundnut oil, State Governments, including Tamil Nadu Government, are not inclined to lift the stocks as originally intended by them. The mode of disposal of the oil is under the consideration of the Government.

C.B.I. Inquiry against Chairman of Syndicate Bank

4974. SHRI VIJAY KUMAR MALHOIRA :

SHRI R.L.P. VERMA :
SHRIMATI SHANTI DEVI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether as reported in the 'Blitz' weekly of 27th August, 1977, a CBI inquiry is pending against Shri K.K. Pai, Chairman of Syndicate Bank for committing a large number of irregularities by making huge grants to Syndicate Agricultural Foundation which spent large amount on the farm of Shri T.A. Pai, former Minister of Industry ;

(b) whether Shri K. K. Pai, Chairman, sanctioned loans to the tune of Rs. 5 crores out of which Rs. 2 crores are unrecoverable and for this act he is under CBI probe ;

(c) if so, the action taken proposed to be taken against the Chairman ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING, (SHRI H. M. PATEL) : (a) Government are aware of a CBI inquiry pending against Shri K. K. Pai, Chairman & Managing Director of the Syndicate Bank. The inquiry against him is regarding certain guarantees issued by the Syndicate Bank on behalf of an advertising concern and not for making huge grants to the Syndicate Agriculture Foundation.

(b) to (d). Shri K. K. Pai, who is working as Chairman and Managing Director of the Syndicate Bank from February 28, 1970, has sanctioned various advances in the discharge of his duties under the powers vested in the Managing Director by the Board of Directors. Government does not know which of these advances make up to Rs. 5 crores referred to in the question and unless the names of the borrowers are made known, it is not possible to indicate what portions of the loans sanctioned are irrecoverable. CBI has not undertaken any probe in the matter of loans sanctioned by the Chairman and Managing Director of the Syndicate Bank. However, on the basis of various allegations received by Government, Reserve Bank have undertaken a scrutiny of the allegations and based on their findings Government will decide on the further course of action in consultation with the Reserve Bank.

**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉगल
मेट्रोलाजी, रांची के तृतीय श्रेणी
और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी**

4975. डा० रामजी सिंह : क्या वारिण्ड्य तथा नागरिक पूति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉगल मेट्रोलाजी, रांची के सभी कर्मचारियों को सेवायें बिहार राज्य से केन्द्रीय सरकार को सौंपी गई थीं ;

(ख) क्या इस प्रकार स्थानान्तरित किये गये ग्रेड तीन और ग्रेड चार के कर्मचारी

1 जनवरी, 1976 से केन्द्रीय सरकार की सेवा में नियमित रूप से नियुक्त किये गये हैं और क्या ग्रेड एक के पद का दर्जा बढ़ा दिया गया है ;

(ग) क्या वर्ष 1970 के बाद नियुक्त किये गये सभी कर्मचारी अब तक तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों के रूप में माने गये हैं ; और क्या निर्धारित नियमों तथा नियमित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये गये एक हैड क्लर्क की सेवायें समाप्त की जा रही हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रेड दो और ग्रेड चार के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने का है ?

वारिण्ड्य तथा नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने भारतीय वैद्य माप विज्ञान संस्थान 1-1-1970 को बिहार सरकार से, अपने नियंत्रण में लिया था। अन्तर्गत तारीख को 28 स्वीकृत पद थे, जिनमें से 3 पद खाली थे। 31-12-69 को 25 पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों में से 20 अस्थायी थे और 5 बिहार सरकार के अन्य विभागों में स्थायी थे। बिहार सरकार ने शुरु में स्थायी कर्मचारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति आधार पर बिना प्रतिनियुक्ति भत्ते के 2 साल के लिये उधार देना स्वीकार किया। उन्होंने 31-12-69 से अस्थायी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दो और भारत सरकार के अंतर्गत अस्थायी नियुक्ति को स्वीकार करना या न करना पूर्णतः कर्मचारियों की इच्छा पर छोड़ दिया। केन्द्रीय सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को तभी रखा जब उन्होंने तदर्थ आधार पर अस्थायी नियुक्ति पर रहना स्वीकार कर लिया।

(ख) और (ग). इन कर्मचारियों को नियुक्ति अस्थायी आधार पर करने का निर्णय किया गया है और इनकी नियुक्तियों की भर्ती